विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) अधिनियम के अन्तर्गत निगमित पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, मान ली गई पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों जो कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की समनुषंगी कम्पनी हैं के प्रबन्धक कर्मियों अर्थात् प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों या प्रबन्धकों (मैनेजर) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 की उपधारा (24) में यथा परिभाषित) के पारिश्रमिक को अधिनियम की अनुसूची XIII के साथ पठित धारा 198, 309 तथा 387 के उपबन्धों के अन्तर्गत नियमित होता है तथापि, केन्द्रीय सरकार को अधिनियमि के उपबन्धों के अन्तर्गत, प्रबन्धकीय कर्मियों की अनुसूची XIII में निर्दिष्ट सीमा से अधिक पारिश्रमिक देने की शक्तयां प्राप्त हैं । अधिनियम के अन्तर्गत निगमित कम्पनियों को विदेशी प्रबन्धकीय कर्मियों के मामले में, प्रत्येक मामले अलग-अलग गुणावगुण के आधार पर, केन्द्रीय सरकार अनुसूची-XIII में किये गये प्रावधानों से अधिक पारिश्रमिक स्वीकृत करती रही हैं । विदेशी प्रबन्ध कर्मियों के पारिश्रमिक को स्वीकृत करते समय आवेदक कम्पनियों में विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी निवेशकों द्वारा आवेदक कम्पनयों को तकनीक उपलब्ध कराने, सम्बन्धित प्रबन्धकीय कर्मी का अनुभव तथा व्यवसायिक विशेषज्ञता, उनके द्वारा अतीत में लिए गए पारिश्रमिक आदि पर पूरा विचार किया जाता है ।

(ङ) प्रबन्ध/पूर्णकालीन निदेशकों या प्रबन्धकों (अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (24) में यथा परिभाषित) के अतिरिक्त ऐसी कम्पनियों के अधिकारियों या कार्मिकों को देय पारिश्रमिक अधिनियम द्वारा निगमित नहीं होता तथा कम्पनियां ऐसे कार्यकारियों/कर्मचारियों का पारिश्रमिक निर्धारित करने को स्वतंत्र हैं ।

गुजरात में लघु उद्योग

2984. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान गुजरात में कितने लघु उद्योगों की स्थापना की गई है और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य को लघु उद्योगों की अतिरिक्त इकाइयों की स्थापना के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है ; और

(घ) इन राज्यों में नए लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार गुजरात में पिछले दो वर्षों के दौरान स्थापित लघु उद्योगों की संख्या इस प्रकार है :-

1990-91	10073
1991-92	11802

वित्तीय वर्षों की स्थापना स्थल व धार सूचना उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, कलेंडर वर्ष 1990, 1991 की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **(नीचे देखिये)**

(ख) जी, नहीं । निजी क्षेत्र में लघु औद्योगिक एककों की स्थापना की जाती है और इसके लिए उद्यमियों द्वारा धन स्वयं जुटाया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नये लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के स्वयं के नीतिगत उपाय होते हैं । वे पिछडे क्षेत्रों में निवेश राजसहायता, बिक्री कर में छूट/आस्थगन और औद्योगिक शेड प्राथमिकता के आधार पर, बिजली/

पावर/टेलीफोन कनेक्शन, कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन सुविधा आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करते हैं । तथापि, विभिन्न सुविधाओं की सीमा तथा स्वरूप प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होता है। भारत सरकार लघु उद्योगों को विपणन में वरीयता तथा लघु उद्योगों में ही निर्माण के लिए मदों के आरक्षण के अलावा उत्पाद-शुल्क में छूट, सावधिक ऋणों पर रियायती ब्याज दर जसे विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन भी देती है ।

विवरण

केलेण्डर वर्ष 1990 और 1991 के दौरान पंजीकृत सीडो एककों की जिलावार संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	पंजीकृत सीडो एककों की संख्या	
		1990	1991
1.	अहमदाबाद	2093	1754
2.	गांधीनगर	55	113
3.	नाडियाड	329	427
4.	बड़ौदा	367	574
5.	भडौंच	326	363
6.	सूरत	586	724
7.	वलसाद	277	241
8.	वापी	168	249
9.	सुरेन्द्रनगर	146	205
10.	राजकोट	1118	924
11.	जामनगर	354	346
12.	भुज	68	177
13.	भावनगर	298	456
14.	अमरेली	85	157
15.	जूनागढ़	134	337
16.	मेहसाना	266	421
17.	साबरकंठा	156	250
18.	बनासकंठा	179	117
19.	पंचमहल	137	208
	योग :	7142	8043

खादी तथा ग्रामोद्योग का उत्पादन

2985. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित वस्तुएं अलोकप्रिय होती जा रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) गत तीन वर्षों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित वस्तुओं की मात्रा कितनी रही है, और

(घ) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की वस्तुएं बेची गई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :
(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन और बिक्री इस प्रकार है :—

(रु० करोड़ में)

	उत्पादन	बिक्री
1989-90	1963.16	2186.73
1990-91	2280.02	2525.14
1991-92	2592.77	2895.33

2986. [*Transferred to 22nd March*, 1993]

Foreign investment in leather industry

2987. SHRI KAMAL MORARKA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposals from foreign companies for manufacture of machinery and components for leather industry;